

an>

Title: Need to clear the arrears of salaries of computer operators in Jharkhand and also regularize the services of para teachers and Gram Rozgar Sevaks in the State.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : मैं सरकार का ध्यान झारखंड प्रदेश में और खासतौर से गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र में टुण्डी, पूर्वी टुण्डी, तोपवांती तथा पीरटांड जैसे सुदूर इलाके की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। झारखंड सरकार ने संविदा के आधार पर पृथक् पंचायत सचिवालय में एक-एक कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली सन् 2011 में की थी जिसका भुगतान 13वें वित्त आयोग के पैसे से किया जा रहा था। वैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की संख्या हजारों में है। वर्ष 2015 में 14वीं वित्त आयोग लागू होते ही उन सभी ऑपरेटरों के भुगतान में अड़चन आने लगी और उनका भुगतान बंद हो गया तथा उनके संविदा को भी रद्द कर दिया गया। ये लोग भुखमरी के कगार पर हैं।

अतः केंद्र सरकार से आग्रह होगा कि अतिलंब उनके बकाए भुगतान की व्यवस्था की जाए तथा 14वीं वित्त आयोग के तहत उन्हें फिर से रखा जाए। इसके साथ ही झारखंड में पारा शिक्षकों तथा ग्राम रोजगार सेवकों की नौकरी भी संविदा के आधार पर है, उन्हें भी समय पर भुगतान नहीं मिलता है। पारा शिक्षक तथा रोजगार को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम के तर्ज पर नियमित किया जाए ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके।